नईदुनिया

चीन में फिर लगेगा लॉकडाउन, सरकार ने बंद किए सभी दफ्तर, नए साल का जश्न मनाने एक हफ्ते की सार्वजनिक छुट्टी घोषित

बीजिंग

दुनिया कोरोना के संकट से उबर चुकी है और खुली हवा में सांस ले रही हैं। अब फिर चीन में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल के लॉकडाउन और मौजूदा लॉकडाउन में जमीन आसमान का अंतर है। आज चीज में जश्न मनाने के लिए करीब एक हफ्ते के लिए सार्वजनिक छुट्टियां दी गई हैं। दरअसल, चीन में नया वर्ष शुरू होने जा रहा है।

चीन के कैलेंडर के मुताबिक 29 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। इस नए साल पर पूरे चीन में जश्न मनाया जाता है।

इसे स्प्रींग फेस्टिवल (वसंत उत्सव) कहा जाता है। इसके लिए सरकार ने पूरे चीन में 28 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक सभी दफ्तर बंद करने का आदेश दिया है। यह उत्सव न केवल चीन बल्कि पूरे पूर्वी एशिया में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है।

यह 15 दिनों तक चलता है। इसमें लाइव परेड और परिवारों के मिलने जैसी सदियों पुरानी परंपराएं शामिल हैं।

2025 में इस साल की शुरुआत 29 जनवरी, बुधवार से होगी। उत्सव 12 फरवरी को समाप्त होगा। चीन का यह नया साल वहां की राशि (जोडियक) से संबंधित है। चीन ने 2025 को सर्प वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है।

चीन के राशि चक्र में सर्प राशि छठे स्थान पर है। यह समझदारी, सुंदरता और भावना का प्रतीक है। सर्प वर्ष में जन्मे लोग आमतौर पर समझदार, आत्मनिर्भर और चुनौतियों को पार करने वाले होते हैं।

आज भी चीन के नए साल पर लाल रंग की सजावट, पटाखे और शोर-शराबे का चलन है। यह बुरी आत्माओं को भगाने और आने वाले साल में शुभता लाने का प्रतीक हैं। चीन नया साल एक पारिवारिक उत्सव होता है।

तमाम लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं। इस त्योहार का प्रमुख आकर्षण पूरे परिवार का एक साथ रात्रिभोज करना है। लोग खूब डांस करते हैं। खुशी मनाते हैं।

न्यूज ब्रीफ

बेंजामिन नेतन्याहू अगले सप्ताह कर सकते हैं व्हाइट हाउस का दौरा

वाशिंगटन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले सप्ताह व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद उनसे मिलने वाले पहले विदेशी नेता होंगे। सीएनएन की खबर के अनुसार, अमेरिका और इजराइल की कूटनीति को करीब से समझने वाले कुछ अधिकारियों ने ऐसे संकेत दिए हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू की यात्रा की योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और ना ही आधिकारिक तौर पर यात्रा के लिए किसी तारीख का चयन किया गया है। अमेरिका और इजराइली अधिकारियों ने यात्रा की योजना को प्रारंभिक चरण बताया है। हालांकि दोनों नेता पिछले सप्ताह टेलीफोनिक चर्चा कर चुके हैं। नेतन्याहू के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें यात्रा के लिए कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ सार्थक बातचीत की है। इस बातचीत में मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा की योजना पर भी चर्चा की गई।

व्यापार विवाद को लेकर कोलंबिया राष्ट्रपति ने की ट्रंप की आलोचना, कहा गोरे गुलाम

वॉशिंगटन। अमेरिका और कोलंबिया के बीच विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए उन्हें गोरे गुलाम बताया है। यह विवाद दोनों देशों के बीच निर्वासित प्रवासियों को लेकर उठे विवाद से पैदा हुआ था, जब कोलंबिया ने अमेरिकी सैन्य विमानों द्वारा निर्वासितों को लाने पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में ट्रंप ने कोलंबिया पर टैरिफ और प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। मीडिया रिपोर्ट में वाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा था कि कोलंबिया इस मुद्दे पर सहमत हो गया है और अमेरिकी सैन्य विमानों को स्वीकार करेगा। इसके बदले अमेरिका ने अपने टैरिफ और प्रतिबंधों को निलंबित कर दिया है। वाइट हाउस के मुताबिक यदि कोलंबिया समझौते का पालन नहीं करता, तो टैरिफ और प्रतिबंधों के मसौदे पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। कोलंबिया के विदेश मंत्री लुइस गिल्बर्टो मुरिलो ने रविवार को इस गतिरोध के समाधान की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हमने अमेरिकी सरकार के साथ गतिरोध को दूर कर लिया है। इस सहमति के तहत अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैरिफ और प्रतिबंधों का मसौदा स्थगित कर दिया है। इसमें कोलंबियाई सामानों पर 25 फीसदी टैरिफ और कोलंबियाई अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध शामिल थे। इससे पहले कोलंबियाई राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने ट्रंप पर तीखा हमला किया।

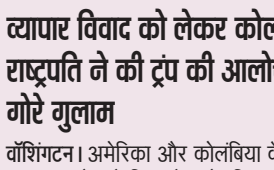

नेपाल ने अमेरिका से आर्थिक मदद न रोकने का आग्रह किया

काठमांडू। अमेरिका की सभी तरह की आर्थिक मदद रोकने की औपचारिक घोषणा ने नेपाल की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल की सबसे बड़ी चिंता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) के तहत मिल रहे आर्थिक सहयोग को लेकर है। नेपाल सरकार ने आधिकारिक रूप से पत्र लिख कर एमसीसी के तहत जारी 55 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सहयोग नहीं रोकने के लिए आग्रह किया गया है। यह पत्र सोमवार को नेपाल के वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूतावास के माध्यम से एमसीसी मुख्यालय भेजा गया है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री विष्णु पौडेल का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अमेरिकी प्रशासन एमसीसी के सहयोग को नहीं रोकेगा। एमसीसी के तहत नेपाल में जो अंतर्देशीय प्रसारण लाइन का काम हो रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पौडेल ने बताया कि उनके पास अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए बने यूएसएआईडी के तरफ से प्राप्त पत्र में आर्थिक सहयोग को तीन महीने के लिए रोकने की जानकारी दी गई है। पत्र में कहीं भी एमसीसी के तहत चल रहे परियोजना का जिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि एमसीसी एक अलग निकाय है। अमेरिकी कांग्रेस ने गरीब देशों में आर्थिक सहयोग के लिए इसे स्थापित किया है। नेपाल को आशंका है कि यूएसएआईडी की तरह एमसीसी की तरफ से डी पत्र आ सकता है। इसलिए नेपाल ने पहले ही एमसीसी मुख्यालय को पत्र भेज दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी से व्हाइट हाउस यात्रा की योजना पर चर्चा

वाशिंगटन

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बातचीत को स्थानीय समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। ट्रंप ने सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात की। दोनों देशों के बीच संबंधों और मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा की योजना पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस ने कॉल के रीडआउट का ब्यौरा जारी किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार, कॉल के दौरान ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को संतुलित करने के प्रयास में अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा, नेताओं ने हमारे देशों के बीच दोस्ती और रणनीतिक संबंधों की ताकत को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा की योजना पर चर्चा की।

दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक, मध्य पूर्व और यूरोप में सुरक्षा पर भी चर्चा और क्वाड गठबंधन के महत्व के बारे में बात की। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। बाइडेन प्रशासन के दौरान भी गठबंधन पर जोर दिया गया था।

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। उन्होंने 2019 में ह्यूस्टन में मोदी के साथ एक विशाल रैली में हिस्सा लिया। फरवरी 2020 में ट्रंप ने भारत का दौरा किया। हजारों लोगों ने ट्रंप का अहमदाबाद में अभिवादन किया। इस बीच एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने फ्लोरिडा से ज्वाइंट बेस एंड्रयूज लौटते समय एयर फोर्स वन विमान में पत्रकारों से कहा कि आज सुबह (सोमवार) उनकी मोदी से लंबी बातचीत हुई। वह संभवत: अगले माह फरवरी में व्हाइट हाउस आएंगे। भारत के साथ हमारे गहरे संबंध हैं।

व्हाइट हाउस ने संघीय अनुदान और ऋण वितरण पर रोक लगाई

वाशिंगटन। व्हाइट हाउस बजट कार्यालय ने सभी संघीय अनुदान और ऋणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के कार्यवाहक निदेशक मैथ्यू वैथ ने कहा, संघीय एजेंसियों को सभी संघीय वित्तीय सहायता के दायित्व या वितरण से संबंधित सभी गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया गया है। सोमवार को भेजे गए एक आंतरिक ज्ञापन में व्हाइट हाउस बजट कार्यालय ने सभी संघीय अनुदान और ऋण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश शाम 5 बजे से प्रभावी होगी। इसका मंगलवार को खरबों डॉलर पर असर पड़ सकता है। यह ट्रंप प्रशासन का संघीय वित्त पोषण पर नियंत्रण स्थापित करने के नवीनतम कदम है। यह आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले सप्ताह के कार्यकारी आदेशों के अनुरूप है।

माइक्रोसॉफ्ट कर सकती है टिकटॉक का अधिग्रहण, ट्रंप ने दिए संकेत

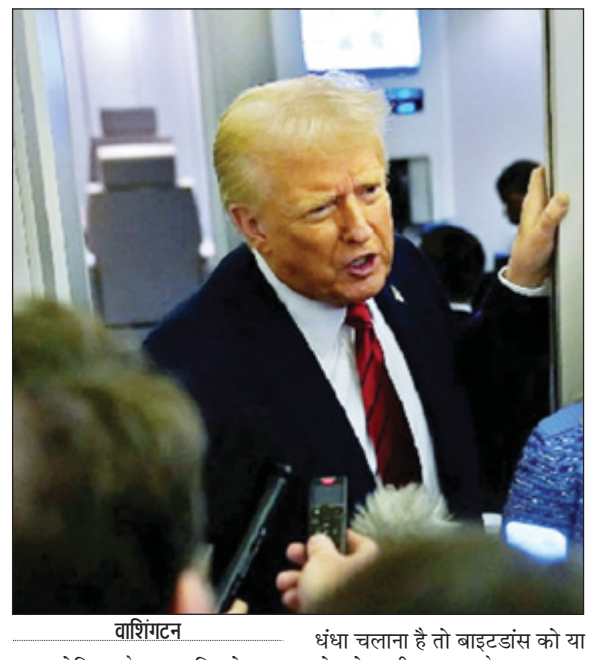

वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक का अधिग्रहण कर सकती है। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उनका मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट, टिकटॉक का अधिग्रहण करने के लिए चर्चा कर रहा है। उन्होंने एयर फोर्स वन में साथ यात्रा कर रहे संवाददाताओं से कहा कि इसकी बोली दिलचस्प होगी।

कानून के अनुसार टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित किया जाना है। ट्रंप ने सीधेतौर पर पूछे जाने पर कि क्या माइक्रोसॉफ्ट इस ऐप हासिल करने के लिए चर्चा कर रहा है ट्रंप ने इस सवाल के जवाब में कहा, मैं हां कहूंगा।

उन्होंने कहा, टिकटॉक में बहुत रुचि है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि टिकटॉक के मौजूदा वक्त में 170 मिलियन अमेरिकी यूजर्स हैं। ट्रंप ने पहले ही यह साफ कर चुके कि अमेरिका में धंधा चलाना है तो बाइटडांस को या तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर बेचना होगा।

अन्यथा प्रतिबंध का सामना करना होगा। 20 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद ट्रंप ने टिकटॉक को 75 दिन की मोहलत प्रदान करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक के तत्कालीन बाइडेन प्रशासन के प्रतिबंध कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि प्रावधान किसी भी तरह के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते।

सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद तब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वह टिकटॉक पर निर्णय लेने से पहले स्थिति की समीक्षा करेंगे।

संघर्षविराम के बाद घरों की ओर लौटते हुए लोग

गाजा में संघर्षविराम के बाद वाहनों के जरिये अपने घरों की ओर लौटते हुए उत्तरी इलाके के लोग।

भारत और नेपाल ने भूकंप के बाद शुरू पुनर्निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

काठमांडू

भारत की मदद से नेपाल में भूकंप के बाद शुरू पुनर्निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा काठमांडू में सोमवार को एक बैठक में की गई। इसमें भारतीय विदेश मंत्रालय के नेपाल डेस्क के प्रमुख अतिरिक्त सचिव मनु महवार और नेपाल के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

नेपाल में अप्रैल 2015 के भूकंप के बाद भारत ने पुनर्निर्माण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान किया था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में आयोजित विशेष सम्मेलन में यह अनुदान चार विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित किया था। आवास निर्माण के लिए 100 मिलियन डॉलर, विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए 50 मिलियन डॉलर, अस्पतालों के निर्माण के लिए 50 मिलियन डॉलर और ऐतिहासिक धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया गया था।

इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए अगस्त 2017 में एक संयुक्त परियोजना निगरानी समिति (जेपीएमसी) तंत्र स्थापित किया गया था।

सोमवार को काठमांडू में जेपीएमसी की पांचवीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद्म कुमार मैनाली ने किया। दोनों पक्षों ने इस बैठक के बाद काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से बयान जारी किया।

रूस ने बनाया अफगान क्वाड गठबंधन, भारत को करना चाहता है शामिल

प्रस्ताव भारत के लिए चुनौतीपूर्ण, चीन, पाकिस्तान और ईरान भी हैं सदस्य

मॉस्को

रूस ने अफगानिस्तान के भविष्य पर क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक नया गठबंधन बनाया है, जिसे अफगानिस्तान क्वाड नाम दिया है। इस गठबंधन में ईरान, पाकिस्तान और चीन जैसे देश शामिल हैं और रूस अब भारत को भी इसमें शामिल करना चाहता है। हालांकि, भारत के लिए यह प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें भारत के दो प्रतिद्वंद्वियों पाकिस्तान और चीन के साथ एक मंच पर बैठना पड़ेगा, जो भारत के रणनीतिक हितों से टकरा सकते हैं।

रूसी विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत इस समूह का हिस्सा बनेगा और इसे अफगानिस्तान में सही कदम बताया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने का भी आग्रह किया। भारत के रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ का मानना है कि पाकिस्तान का हिस्सा होना भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण हैं। अफगान क्वाड का गठन तब हुआ जब अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद क्षेत्रीय देशों को अफगानिस्तान की स्थिरता और सुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ी।

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और भारत के लिए अफगानिस्तान की स्थिरता साझा क्षेत्रीय हित हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी इस गठबंधन में भारत के शामिल होने के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। भारत ने अब तक तालिबान के साथ बहुत कम संवाद किया है, लेकिन रूस का निमंत्रण इस्लामाबाद और काबुल के बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत को इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

साइबर-स्कैम केंद्रों में फंसे 67 भारतीय आजाद, लाओस में भारतीय दूतावास ने की मदद

वियनतियाने। भारतीय दूतावास ने लाओस के बोकेओ प्रांत स्थित गोल्डन ट्राइंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन (जीटीएसईएड) से 67 भारतीयों को बचाया। ये सभी युवा साइबर-स्कैम केंद्रों में धोखाधड़ी और तस्करी का शिकार हो गए थे, जहां उन्हें अपराधी समूहों द्वारा काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। भारतीय युवाओं को इस संकट से बाहर निकालने की कार्रवाई भारतीय दूतावास के प्रयासों का नतीजा है। इन भारतीय युवाओं ने मदद के लिए दूतावास से संपर्क किया, तो दूतावास ने उनकी मदद के लिए कदम उठाए। दूतावास अधिकारियों ने जीटीएसईएड का दौरा किया और लाओस के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर युवाओं को मुक्त कराया। इसके बाद उन्हें विएंतियाने स्थित दूतावास लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई, और उनके रहने और खाने की सुविधा भी प्रदान की। भारत के राजदूत ने इन युवाओं से मुलाकात की और उनकी कठिनाइयों के बारे में बातचीत की।